projects and the time-frame of their con pletion are given below:—

Project	Anticipated capital cost (Rs. in lakhs)	Expenditure incurred till July '91 (Rs. in lakhs)	Time-frame of completion
HPT, Barmer . .	928.75	331.56	1994-95
HPT, Bundi . . .	442.00	156·54	1992-93
HPT, Jaisalmer . .	648.25	428·38	1993-94

1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के कोटे का पुनः निर्धारण

554. **श्री राघवजी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को चीनी, डीजल, मिट्टी के तेल, गेहूं और तेल आदि के कोटे को पुनः निर्धारित करने जा रही है ;

(ख) यदि हां तो ऐसा पुनः निर्धारण कब तक किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न का आवंटन राज्यों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध स्टाक, उन वस्तुओं की बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है।

लेवी चीनी का आवंटन, 1-10-86 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति महीना 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । तथापि, जुलाई, 1991 में केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक लेवी चीनी के आवंटन में 5 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है । इसके बाद स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी ।

आयात में कमी के कारण इस समय आयातित खाद्य तेल का कोई नियमित आवंटन नहीं किया जा रहा है ।

मिट्टी के तेल का आवंटन गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आवंटन में उपयुक्त दर से वृद्धि करके किया जाता है । इसके आवंटन में वृद्धि मिट्टी के तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

केन्द्रीय पूल से किए जाने वाले सभी आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है ।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप

555. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप बंधन के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे,

(ख) वे लक्ष्य किस हद तक प्राप्त कर लिये गये हैं ; और

(ग) इस समय महाराष्ट्र में कितने नलकूप लगा दिये गये हैं और इनसे कितना क्षेत्र लाभान्वित हुआ है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) लघु सिंचाई योजनाओं की आयोजना बनाने, उन्हें वित्त पोषित

करने और कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारें अपने योजना संसाधनों में से करती हैं और उनकी केन्द्र सरकार से तकनीकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती है । राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में नलकूपों की बोरिंग के योजना-वार लक्ष्य केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में प्रगति की निगरानी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराये गए गांवों की संख्या और लाभान्वित जनसंख्या के आधार पर की जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों की बोरिंग के बारे में सूचना नहं रखी जाती है ।

Pilot projects for safe drinking water

556. SHRI JAGADISH JANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some pilot projects have lueen implemented in different states to provide safe drinking water to the villagers;

(b) if so, the number of pilot projects implemented in different states during the last three years;

(c) the states where those pilot projects ihave been implemented;

(d) whether any such pilot project has been implemented in Orissa in the last three years; and

(e) if so, the achievements thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) There are 55 Mini Mission Projects under implementation during the last 3 years in various districts of 25 States and Union territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and Pondicherry.

(c) The pilot projects have been taken up for implementation in the selected districts in all the States. However, the entire State of Goa is covered under the Mini Mission Programme.

(d) The Mini Mission Projects being implemented in Orissa are in Phulbani end 5 blocks of Ganjam, Koraput and Mayurbhanj districts.

(e) The achievements in the Mini Missions in Orissa are as under:—

(Rs. in lakhs)

S.No.	Mini Mission	Project cost approved	Funds released by by Central Govt.	Expenditure upto June, 1991.
1	Koraput . .	626.50	413.00	286.25
2	Mayurbhanj . .	104.10	80.00	78.37
3	Phulbani & 5 Blocks of Ganjam District	417.54	268.20	190.87

Physical Progress

Koraput

Source Finding was completed for 784 sites. 520 'No Source' Problem villages have been covered. 614 handpump tube wells and 2 sanitary wells have been completed. 761 water samples have been tested and 97 iron removal plants have been installed.